भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2394
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

2394. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछुआरों को सुरक्षा और समुद्री सीमाओं के मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने अथवा अवगत कराने के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोंदिया के मछुआरे समुद्री सीमा और पड़ोसी देश की सीमा पार करने के कारण काफी हद तक प्रभावित हुए थे; और

(घ) क्या सरकार इन मुद्दों का समाधान ढूंढेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): जी हाँ, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ नॉटिकल एंड इंजीन्यरिंग ट्रेनिंग' (सिफनेट) की स्थापना की है, जो मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और समुद्र में जाने वाले फिशिंग वेसल्स पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित मैनपावर तैयार करता है। संस्थान का मुख्यालय कोच्चि में है और चेन्नई और विशाखापत्तनम में इसकी दो और इकाइयाँ हैं। संस्थान आउटरीच/इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मछुआरों के लिए समुद्र में सुरक्षा, सीमैनशीप और नेविगेशन, जिम्मेदारीपूर्ण मत्स्यन और समुद्र में नेविगेशन और संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि पर विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है महाराष्ट्र में गोंदिया जिला चारों ओर भूमि से घिरा है, और इस जिले में मीठे पानी में मत्स्यपालन किया जाता है। मत्स्यपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, गोंदिया जिले के निवासी के फिशिंग वेसेल्स में चालक दल के सदस्य के रूप में कार्यरत होने या पड़ोसी देश की समुद्री बाउंड्री या सीमा पार करने के कारण प्रभावित होने की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ): प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने मरीन फिशिंग वेसेल्स के मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सरवेल्लेंस के लिए 'नेशनल रोलआउट प्लान फॉर वेस्सेल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम' परियोजना को मंजूरी दी है। नेशनल रोलआउट प्लान में 364 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मरीन फिशिंग वेसेल्स पर लगभग एक लाख ट्रांसपोंडर लगाने की परिकल्पना की गई है। यह एक टू-वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे 200 एनएम की दूरी तक मछली पकड़ने के लिए गए मछुआरे अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन का उपयोग करके छोटे मैसेज भज सकते हैं । इसमें जियोफेंसिंग की सुविधा भी है और जिससे समुद्री सीमा के पास पहुंचने या उसे पार करने के अनजाने उल्लंघन से बचाव के लिए मछुआरों को अलर्ट किया जा सकता है।

*****